RAJYA SABHA

Wednesday, the 5th March, 1997/ 14the Phalguna, 1918 (Saka)

The House met at eleven of the clock Mr. Chairman *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Flood Control In Bihar

*161. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration to stop damage caused by floods in Bihar every year due to rivers flowing from Nepal;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Ganga Flood Control Commission has prepared comprehensive flood management plans for all sub-basins of Ganga, in respect of all concerned States including those tributaries flowing from Nepal to Bihar, and sent to the State Governments for their detailed investigation and implementation. The State Government of Bihar has been undertaking various flood management measures which have provided reasonable degree of protection to an area of 18.89 lakh. ha. out of a flood prone area of 42.60 lakh ha. so far. The schemes are undertaken bv the State out of the State plan fund's depending on the *interse* priority decided by them. ' The Central Government is also providing financial assistance to Bihar for implementing flood proofing programme in the State during 8th Plan which is proposed for continuation during 9th Plan. 98 flood proofing schemes have been cleared and an amount of Rs. 1.5 crore was released during 1995-96 to the State as advance for initiating the work. However so far the State Government has spent only Rs. 27 lakh. During 1996-97 this Ministry had provided for Rs. 7 crore but in view of poor expenditure, while finalising revised estimates, it has been reduced to Rs. 1 crore, the release of which would depend upon utilisation certificate for the year 1995-96.

The Central Government is also holding discussions with the His Majesty's Government of Nepal regarding construction of storage reservoirs and embankments on common rivers which would benefit both the countries. Extending embankments on Lalbakeya, Kamla, Bag-mati and Khando rivers into Nepal territory are under active consideration and the work on Lalbakeya embankment is expected to start very early. Investigations for Sapta Kosi High Dam in Nepal are also expected to be taken up jointly with Nepal shortly. A joint project for setting up meteorological and hydro meteorological stations on common rivers with laval which would provide data for effcient flood forecasting on these rivers in under implementatioa.

श्री गया सिंह : माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया वही हैं जो पहले से जवाब आ रहा हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह समस्या क्योंकि अभी हाल में आपने बंगला देश

और भारत का जो एक एतिहासिक समझौता किया था उससे बंगला देश को तो लाभ होगा, राजनीतिक तौर पर हिन्दुस्तान को भी लाभ होगा । लेकिन पिछले वन डिकेड से नेपाल में बारिश होती हैं और बिहार के 10-12 जिलों में बाढ़ हो जाती हैं । बिहार में बारिश नहीं भी हुआ तो भी बिहार में नेपाल के पानी के चलते बाढ़ आ जाती हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से जो मंत्री जी ने जवाब दिया हैं, यह जानना चाहता हूं कि एट्थ फाईव ईयर प्लान की इन्होंने चर्चा की और यह कहते हैं नाईर्थ फाईव ईयर प्लान में यह कंटीन्यू करेगा लेकिन मुख्य रुप से हमारा सवाल हैं कि यह जो पिछले आजादी के बाद से हर साल लाखों आदमी धर-द्वार छोड़कर बाढ़ के चलते 6 महीना बाहर रहते हैं, तो क्या इतने महत्वपूर्ण इस विषय पर संयुक्त मोर्चा की सरकार और आपका मंत्रालय निकट भविष्य में नेपाल से कोई समझौता करने का इरादा रखता है या उस संबंध में कोई अभी तक आफिशियल मीटिंग हुई हैं या क्या प्रोग्रेस हैं, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी, पिछले 60 दशक से नेपाल से बहने वाली नदियों के बाढ़ ओर उनकी समस्याओं के बारे में नेपाल से बातचीत की कोशिश हो रही हैं । महाकाली संधि के बाद दरवाला अब खुला हैं, क्योंकि उससे पहले नेपाल का रूख अनुकूल नहीं होता था । उसके बाद नेपाल के जल संसाधन में बातचीत हुई हैं और उसकी अधिकारियों के तौर पर इसकी बातचीत चल रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल की नदियों से बिहार में जो बाढ़ आती हैं उनके लिए हम जल्द कोई रास्ता और परियोजना निकालेंगे ।

श्री गया सिंह : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने तो कोई स्पष्ट नहीं कहा, जैसा जनरल जवाब पिछली बार दिया था वही दिया हैं । मैं फिर आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पष्ट रूप से एक ही सवाल कर रहा हूं । क्या आपके हिसाब से 1997 तक मंत्री लेविल तक नेपाल से कोई बातचीत हो सकेगी जब आप इतना महत्वपूर्ण समझते हैं, और दूसरा, इसी के साथ कि कोशी में जो बांध 1955 में बनाया गया था वह नेपाल के पानी और उसके साथ मिट्टी के चलते बांध नदी के बराबर होता जा रहा हैं । क्या उसके संबंध में भी कुद करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, 1955 के बने हुए बांध की अब मियाद पुरी हो चुकी हैं ओर यह सही हैं कि नेपाल से बहने वाली नदियां अपने साथ रेत और गाद बहुत लाती हैं । उसके हल करने के लिए हमें नेपाल से ही सम्पर्क करना पड़ेगा । नेपाल हर बात में सतर्क रहता हैं और इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाती हैं और यह बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात हैं । आज मुझे अच्छा यह लग रहा हैं कि माननीय सदस्य की मैं प्रशंसा करुगा कि आम तोर पर बाढ़ के सवाल को जब बाढ़ आती हैं तभी पार्लियामेंट से लेकर देश की जनता तक बहस करती हैं ।

लेकिन आज बिना मौसम के यह बहस हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि जब कोई समस्या आती हैं तो उसके आंतक के कारण हम लोग उस समस्या का निदान नहीं कर पाते हैं और उसके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं । आज जब इस समस्या पर सोचा जा रहा हैं बाढ़ के अलावा वाले समय पर तो सारा प्रयास यही हो रहा हैं कि नेपाल सरकार से बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाए और कोई योजना तैयार की जाए ।

श्री जलालुदीन अंसारी : माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि नेपाल से जो बाढ़ का पानी आता हैं, उससे बहुत सारी बालू और दूसरी चीजें आती हैं और हमारे बिहार का वह हिस्सा प्रतिवर्ष तबाह और बरबाद हो जाता हैं । सरकार बराबर कहती रही, पूर्ववर्ती सरकार भी कहती रही हैं और हमारे माननीय मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम नेपाल से इस संबंध में बातचीत करेंगे । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन होगा कि यह तो वर्षों से आश्वासन मिल रहा है कि नेपाल सरकार से बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाएगा लेकिन दुख की बात हैं कि अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाला जा सका हैं । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि बिहार की इस भयानक बरबादी को रोकने के लिए और राहत देने के लिए नेपाल सरकार से बातचीत करके आप एक समझौता करें ताकि इस विभीषिका से बिहार की जनता को राहत मिल सके । मैं आश्वासन चाहूंगा कि इस दिशा में वे कौन सा प्रयास करने जा रहे हैं, यह सदन को बताने का कष्ट करें ।

†**شری جلال الدین انصاری :** مانیہ سبھا پتی مہودے۔ منتری جی نے سویکار بھی کیا ہے کی نیپال سے جو باڑھ کا پانی آتا ہے، اس سے بہت ساری بالوں اور دوسری چیزیں آتی ہے اور ہمارے بہار کا وہ حصہ

†Transliteration in Arabic Script

پرتی ورش تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ سرکار برابر کہتی رہی، پوروتی سرکار بھی کہتی رہی ہے اور ہمارے منتری جی بھی کہہ رہے ہیں کی ہم نیپال سے اس سمبندھ میں بات چیت کرینگے۔ میرا مانیہ منتری جی سے نویدن ہوگا کی سرکار تو ورشوں سے آشواسن مل رہا ہے کہ نیپال سرکار سے بات چیت کرکے کوئی راستہ نکالا جائیگا۔ لیکن دوکھ کی بات ہے کی ابھی تک کوئی راستہ نہیں نکلا جا سکا ہے۔ میں مانیہ منتری جی سے چاہونگا کی بہار کی اس بھیانک بربادی کو روکنے کے لئے اور راحت دینے کیلئے نیپال سرکار سے بات چیت کرکے آپ ایک سمجھوتا کریں تاکہ اس وبھیشیکا سے بہار کی جنتا کو راحت مل سکے۔ میں آشواسن چاہونگا کی اس دیشا میں وہ کون سا پریاس کرنے جا رہے ہیں، یہ سدن کو بتانے کا کشٹ کریں۔

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी, अभी बातचीत अधूरी ही हैं और कोशिश इस बात की की जा रही हैं कि कोसी बांध माननीय गया सिंह जी ने उल्लेख किया, उसे और ऊंचा किया जाए और इसके लिए बात हो रही हैं । नेपाल सरकार अगर सहमत हो जाती हैं और मेरा ऐसा विश्वास हैं कि वह शीघ्र ही सहमत हो जाएगी तो बाढ़ को रोकने के लिए उसको ऊंचा करने की योजना बनाई जाएगी ।

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे : माननीय सभापति जी नेपाल से हो या हिमालय से जो नदियां आती हैं, वे हीं, उन नदियों से हर साल बड़ी मात्रा में बाढ़ आती हैं और उसके कारण बिहार, बंगाल और असम में बहुत ही नुकसान होता हैं । हर साल जमीन, खेती उत्पादन और नदीं के किनारे उसे गांव हो या शहर हों, उनको करोड़ो रुपए का नुकसान होता हैं । इन सबको रोकने के लिए और पानी से सिंचाई के लिए बहुत ही फायदेमंद गंगा-कावेरी योजना जो डा. के.एल. राव ने जो कि प्रख्यात इंजीनियर थे, उन्होंने प्रस्तावित की थी । अभी सरकार की जो म्लोबलाइज़ेशन और लिब्रलाइजेशन की पालिसी हैं, उसके आधार पर सरकार क्या इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी, गंगा-कावेरी योजना तो दूसरा विषय होगा, इसके लिए अलग नोटिस की जरुरत हैं । जहां तक नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बिहार को होने वाले नुकसान कासवाल हैं, मैंन पहले ही कहा कि इस विषय पर वार्ता बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा ।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि बिहार में करीब 98 फ्लड-प्रूफिंग स्कीम्स सैंक्शन की गई हैं जिसके लिए डेढ़ करोड़ रुपया दिया गया था लेकिन बिहार सरकार ने सिर्फ 27 लाख रुपए का उपयोग किया । 1996-97 से मंत्रालय 7 करोड़ रुपए देना चाहता था लेकिन पिछली पूअर परफॉरमेंस को मददे-नज़र रखते हुए उसे घटा कर 1 करोड़ कर दिया गया । आपने इस पर विचार-विमर्श करने के लिए या इसकी मॉनीटरिग करने के लिए कभी कोई उच्च-स्तरीय दल भेजा हैं और उसने क्या रिपोर्ट पेश की हैं, कृपा करके यह बात दें ।

दूसरे, क्यां मंत्री महोदय को पता हैं कि लालबाकेया, कमला, बागमती और खाण्डों नदियों पर हम महाकाली संधि के बाद यह उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ उसके एम्बैंकमेंट्स को बढ़ाने के लिए या उसके पानी को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था की जाएगी ? पर नेपाल की चीन से भी कुद संधिया हुई हैं और चीन ने उनको की कुछ प्रपोजल दिये हैं कि वह इन नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न करेगा और बिजली उत्पादन से नेपाल के चारों तरफ जो सड़क बन रही हैं उसमें लाइट की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और दूसरी सारी व्यवस्थाओं का संचालन होगा । बिजली उत्पादन केन्द्र बनने से वहां पानी की छूट में और उसके रुकाव में टाइम-टाइम पर खतरा पैदा हो सकता हैं । नेपाल के तराई इलाकों में जहां बिहार बसा हुआ हैं, उसके बारे में आपने कोई जांच पड़ताल की हैं और अगर की हैं तो नेपाल से इस संबंध में क्या बात की हैं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : फ्लड प्रूफिंग के कार्यक्रम मे जो बिहार सरकार की तरफ से शिथिलता आई है कि उसने

डेढ़ करोड़ में से केवल 27 लाख रुपये खर्च किये । जब तक उपयोग करने का, यूटीलिटी सटीफिकेट जिसको कहते हैं, प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता हैं जब तक धन निर्मुक्त करना मुश्किल हैं और इसीलिए आम तौर पर इस तरह के कार्यक्रम में राज्य सरकारों की दिलचस्पी कम रहती हैं । फिर भी मुजफ्फरपुर और पोनिया जिले में फ्लड प्रूफिंग का कार्यक्रम चल रहा हैं और फ्लड प्रूफिंग के काम को आगे बढ़ाने और मानिटरिग के लिए अभी एक मीटिंग वहां के ऐक्सपर्ट्स की बुलाई गयी हैं और हम समझते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा । रह गयी बात नेपाल से बहने वाली तीन-चार नदियों की, उनके बारे में नेपाल सरकार से हम लोगों ने तटबंध को और ऊंचा बढ़ाने की बात की थी, खास तौर से वहां के जल संसाधन मंत्री से । उन्होंने भी इस सम्बन्ध में सहमति जताई हैं । कुछ नदियां जो तिब्बत से बहकर आती हैं, उसके बारे में चीन से उनकी बातचीत हुई होगी और वह हमारे मंत्रालय और सरकार का विषय नहीं हैं, यह विदेश विभाग ही बात सकता हैं कि क्या बातचीत हुई हैं ।

Bridges on National Highways in Uttar Pradesh

*162. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister, of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the number of bridges constructed on National Highways in Uttar Pradesh during the last three years;

(b) the number of bridges proposed to be constructed during the current year together with the details thereof; and

(c) the target proposed to be fixed for construction of bridges during the Ninth Five Year Plan?

MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) Five number of bridges were constructed on National Highways in Uttar Pradesh during the last three years.

(b) Five bridges are targetted to be completed during the current yer (1996-97). The details thereof are as under:—

(1) Bridge over Sarain river on Sitapur bypass on NH-24.

(2) Khajuri bridge in Km. 70 of NH-29.

(3) Mcghai bridge in Km. 88 of NH-29.

(4) Ami bridge in Km. 188/2 of NH-29.

(5) Taraina bridge in km. 165 of NH-29.

(c) The 9th Five Year Plan is yet to be finalised.

श्रीमती मालती शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी के भाग "ग" के उत्तर में मैं यह पूछना चाहती हूं कि नवी पंचवर्षीय योजना में क्या दिल्ली से हरिद्वार तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की कोई योजना हैं ? दूसरा, स्टेट हाईवेज़ में भी क्या यह योजना हैं कि पानीपत से खटीमा मार्ग जो तितावी शुगर मिल के पास से होकर गुजरता हैं, वहां हिंडन नदी का एक पुल हैं कि इससे अधिक भार इस पुल के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए ? लेकिन एक तो वह पुल सिंगल हैं और उसके नीचे के तमाम वैल्डर कट चुके हैं । एक बार वहां दुर्घटना हो चुकी हैं और भविष्य में भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना हैं जब कि तितावी शुगर मिल का सारा गन्ना वहां से गुजरता हैं और हरियाणा को जाने वाला पूरा ट्रैफिक भी वहां से गुजरता हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि केन्द्र की सरकार जो दो वर्ष से उत्तर प्रदेश में हैं, क्या इस मार्ग और इस पुल की तरफ तुरन्त ध्यान देकर आप यह बताएंगे कि नवीं पंचवर्षीय योजना में इसके निर्माण की कोई योजना आपके पास हैं ?

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Sir, generally, so far as declaration of the highways is concerned, we have not declared any highways because of financial crunch. After the budgetary allocation I find that there is some relief. I will think over, consider the project which the hon. Member has mentioned.

With regard to the Delhi-Hardwar State highway, it is with the State. There-tore, the State Government has to take care of it. I will also take into considera- . tion the bridge at Panipat, which the hon. Member has mentioned.

श्रीमती मालती शर्मा : एक प्रश्न जो इसी का महत्वपूर्ण भाग एक था कि दिल्ली से हरिद्वार एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की बात हैं इसका उत्तर मैं मंत्री जी से चाहती हूं । कुम्भ मेला आने वाला हैं और इस रास्ते